



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 5-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 11, 2018 (PAUSA 21, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 जनवरी, 2018

संख्या 15/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 109 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:-
“109क. अपील प्राधिकारी की नियुक्ति—(1) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तिथि, जिसको उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, से तीन मास के भीतर,—

(क) राज्य कर आयुक्त को अपील कर सकता है, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो;

(ख) राज्य कर अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश राज्य कर संयुक्त आयुक्त तक के रैंक के अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

(2) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 107 की उप-धारा (2) के अधीन निदेशित कोई अधिकारी, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तिथि से छह मास के भीतर—

(क) राज्य कर आयुक्त को अपील कर सकता है, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो;

(ख) राज्य कर अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश राज्य कर संयुक्त आयुक्त तक के रैंक के अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

(3) राज्य कर आयुक्त अभिलिखित किए जाने वाले प्रशासकीय कारणों से, किसी अपील को एक अपील प्राधिकारी से किसी अन्य अपील प्राधिकारी को अन्तरण कर सकता है या अपील के सारभूत समरूप आधारों के उत्पन्न होने पर अपील के बहुलित मामलों को क्लब कर सकता है और उन्हें अपील प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकता है।”।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 11th January, 2018

No. 15/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2018.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, after rule 109, the following rule shall be inserted, namely:-

“109A. Appointment of Appellate Authority- (1) Any person aggrieved by any decision or order passed under the Act or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) may appeal to –

- (a) the Commissioner of State Tax where such decision or order is passed by the Additional Commissioner of State Tax;
 - (b) the Additional Commissioner of State Tax (Appeals) where such decision or order is passed by the officer upto the rank of Joint Commissioner of State Tax, within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person.
- (2) An officer directed under sub-section (2) of section 107 to appeal against any decision or order passed under the Act or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) may appeal to –
- (a) the Commissioner of State Tax where such decision or order is passed by the Additional Commissioner of State Tax;
 - (b) the Additional Commissioner of State Tax (Appeals) where such decision or order is passed by the officer upto the rank of Joint Commissioner of State Tax, within six months from the date of communication of the said decision or order.
- (3) The Commissioner of State Tax may transfer an appeal from one appellate authority to another appellate authority on an administrative ground to be recorded in writing or may club multiple cases of appeal arising out of substantive similar grounds of appeal and assign them to one appellate authority.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.